

प्रेषक,

जे०पी० जोशी
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग-2

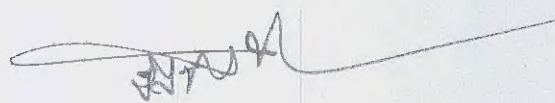
देहरादून: दिनांक 05 अगस्त, 2015

विषय: इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देहरादून को ग्राम ब्राह्मणगांव, परगना पछवादून, तहसील सदर, जनपद देहरादून में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (डी.आई.टी. विश्वविद्यालय परिसर के विकास/विस्तार हेतु) कुल 1.3042 है० भूमि कय की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं०-687/12ए-65/(2014-2017)/डी.एल.आर.सी., दि० 16-7-2015 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, देहरादून को ग्राम ब्राह्मणगांव, परगना पछवादून, तहसील सदर, जनपद देहरादून में स्थित खसरा संख्या-63ख, 73, 76, 77क, 10ख, 69ख 70, 71क, 71ख, 72क एवं 74 की कुल 1.3042 है० भूमि को शैक्षणिक प्रयोजनार्थ (डी.आई.टी. विश्वविद्यालय परिसर के विकास/विस्तार हेतु) कय किए जाने की अनुमति, उत्तराखण्ड (उ०प्र० जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दि० 15.01.2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- क्रेता धारा-129 ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- क्रेता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन (डी.आई.टी. विश्वविद्यालय परिसर के विकास/विस्तार हेतु) के लिये करेगा, जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होगा।
- 3- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।



- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है, उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 5- शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी।
- 6- इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग मात्र शैक्षणिक प्रयोजन (डी.आई.टी. विश्वविद्यालय परिसर के विकास/विस्तार हेतु) हेतु ही किया जायेगा।
- 7- स्थल पर निर्माण प्रचलित उप विधि के अनुसार किया जायेगा तथा भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के अनुसार पहुंच मार्ग उपलब्ध कराया जायेगा।
- 8- शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धांतों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निर्माण का प्लान सीडा/विनियमित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत कराना आवश्यक होगा।
- 9- जिलाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि भूमि के प्रस्तावित अन्तरण से किसी राजस्व विधि/नियमों का उल्लंघन न हो तथा प्रस्तावित भूमि भारमुक्त/बन्धक मुक्त होने एवं विवाद रहित होने पर ही क्रय की जाय।
- 10- सम्बन्धित इकाई द्वारा भू-उपयोग करने से पूर्व सक्षम एजेन्सी (विनियमित क्षेत्र प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विकास प्राधिकरण) से नियमानुसार अनापत्ति प्राप्त करनी होगी तभी वह भूमि का उपयोग निर्धारित कार्य हेतु कर सकेंगे।
- 11- किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।
- 12- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 13- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।
- 14- सम्बन्धित इकाई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के संचालन से पूर्व सम्बन्धित विभागों से मान्यता/अनापत्ति प्राप्त कर ली जायेगी।
- 15- उपरोक्त प्रतिबन्धों/शर्तों का पूर्णतः अनुपालन न होने पर तथा भिन्न उपयोग करने, उल्लंघन होने की दशा में अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से भी ससमय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

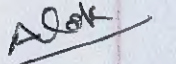
(जे०पी० जोशी)
अपर सचिव।

प्र०सं० 2094/XVIII(II)/2015-1 (21)/2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4- वाईस चेयरमैन, इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज, 21-न्यू कैन्ट रोड, हाथीबड़कला, देहरादून।
- ✓ 5- निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6- प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय, देहरादून।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(आलोक कुमार सिंह)

अनु सचिव।